भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
(दीपम)

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *17
सोमवार 1 दिसंबर, 2025
10 अग्रहायण, 1947 (शक)

आईडीबीआई बैंक का रणनीतिक विनिवेश

***17. श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतरावः**
श्री सुधीर गुप्ताः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का आईडीबीआई बैंक का रणनीतिक विनिवेश करने का कोई प्रस्ताव/योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया कब तक पूरी होने की संभावना है;

(ग) क्या किसी विदेशी बैंक/वित्तीय संस्था ने आईडीबीआई बैंक के अधिग्रहण में रुचि दिखाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आईडीबीआई बैंक के इस रणनीतिक विनिवेश से सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कितना राजस्व सृजित/अर्जित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या सरकार ने आईडीबीआई बैंक के प्रस्तावित विनिवेश के बारे में आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए उनकी यूनियनों और परिसंघों से परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्री
(श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (ङ) वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया है।

******

'आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक विनिवेश' के संबंध में दिनांक 01 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *17 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित वक्तव्य

(क) और (ख) आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने दिनांक 05.05.2021 को हुई अपनी बैठक में आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक रूप से' अनुमोदन प्रदान कर दिया है, जो कि भारत सरकार और एलआईसी में शेयरधारिता की उस सीमा तक होगा, जो एलआईसी के साथ परामर्श करके और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा नियत फ्रेमवर्क के भीतर तय किया जाएगा।

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ रणनीतिक विनिवेश करने के लिए मई 2021 में सीसीईए (आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति) के अनुमोदन के अनुसरण में, प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ रणनीतिक विनिवेश करने के लिए 60.72% आईडीबीआई बैंक इक्विटी की पेशकश की जा रही है, जिसमें भारत सरकार 30.48% की पेशकश कर रही है (बिक्री के पश्चात भारत सरकार की अधिशेष इक्विटी 15% हो जाएगी) और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) विनिवेश के लिए 30.24% इक्विटी की पेशकश कर रही है (बिक्री के पश्चात एलआईसी की अधिशेष इक्विटी 19% हो जाएगी)।

संभावित बोलीदाताओं से रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करने के लिए दिनांक 7 अक्तूबर, 2022 को प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) प्रकाशित किया गया था। पीआईएम पर प्रतिक्रिया के रूप में विभिन्न रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्राप्त हुईं थी। इन ईओआई को सुरक्षा अनापत्ति के लिए गृह कार्य मंत्रालय (एमएचए) को और 'सही और उचित' मूल्यांकन के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) को भेज गया था। गृह मंत्रालय से सुरक्षा अनापत्ति और आरबीआई से 'सही और उचित' मूल्यांकन कि मंजूरी मिलने के बाद, यह सौदा अभी चुने गए बोलीदाताओं (एसबी) द्वारा उचित अध्यावसाय के चरण में है।

(ग) मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार, सौदा पूरा होने से पहले बोलीदाताओं की पहचान नहीं बताई जा सकती।

(घ) और (ङ) भारत सरकार और एलआईसी को मिलने वाली रकम की प्राप्ति बोली पर निर्भर करती है और इसलिए अभी इसकी जानकारी नहीं है। रणनीतिक बिक्री के निबंधन और शर्तें निर्धारित करते समय, मौजूदा कर्मचारियों और अन्य शेयरधारकों की वैध चिंताओं को शेयर खरीद करार (एसपीए) में किए गए उचित प्रावधानों के माध्यम से उचित रूप से संबोधित किया जाता है।

******